



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1982/कार्तिक 25, 1904

No. 194]

NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 16, 1982/KARTIKA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 55-आई टी सी (पोएव)/82

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1982

विषय:—भारतीय रेलवे विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन
2.68 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के संबंध
में लाइसेंस शर्तें।

मिस्त्र सं० आईपीसी/23(35)/82.—विदेशी आर्थिक सहयोग निधि/
ऋण करार सं० आईडी-पी, 17 (भारतीय रेलवे विकास परियोजना)
के अन्तर्गत येन 2.68 बिलियन के माल और सेवाओं का आयात करने
के संबंध में आयात लाइसेंस जारी करने से संबंधित जैसी शर्तें इस सार्व-
जनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें जानकारी के लिए अधि-
सूचित किया जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 55-आई० टी० सी०
(पी० एन०)/82, दिनांक 16 नवम्बर 1982 का परिशिष्ट (1)

भारतीय रेलवे विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 2.68
बिलियन ऋण के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंस
शर्तें।

खण्ड-1. सामान्य शर्तें:—

(1) भारतीय रेलवे विकास परियोजना की आयात आवश्यकताओं
के विस्तार के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ)

द्वारा प्रदान किया गया 2.68 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों
के लिए खुला है तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली
वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों
से आयात की जा सकती हैं। ये देश इन ऋण के अन्तर्गत पात्र छोन
वेश होंगे।

1. (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी
विकास पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निरासी कर दी गई हो।
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों का मूल्य येन 3,000
मिलियन (सात-बीना-भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूप में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि
को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई
सार्वजनिक सूचना सं० 78 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून,
1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में सकेतित दर पर निर्धारित
किया जाएगा जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी
और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस(नो) में विनिर्दिष्ट
मुद्रा विनिर्देश दर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नाम डालेंगे। लाइसेंस
पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई टी सी (17)" होगा।
प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जेसी" कोड होगा
भारतीय रेलवे को आयात लाइसेंस भेजने समय मुख्य नियंत्रक, आयात-
निर्यात के पक्ष में भी इसे दुहराया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को प्लॉकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल भारतीय रेलवे के नाम में आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) भारतीय रेलवे की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 3,000 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) में अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि भारतीय रेलवे द्वारा आवेदन करने पर 31.12.86 तक दी जा सकती है। हमले आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस में मगन माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट स्थापित हों, तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकारों के कमिशन के प्रति कोई भी भूतान भारतीय अधिकारों को भारतीय रूप में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भूतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रूप में भारत में किया जाएगा।

“पक्के आदेशों का अर्थ” विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारकों द्वारा दिए गए उन कय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विशिष्ट हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विशिष्ट हस्ताक्षरित कय संविदा हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अधिकारियों के आदेश और या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टि-करण आदेश स्वीकार्य नहीं हैं।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर डेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि डेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, इन्ड्यू ई 1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इस कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करे।

आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पक्षता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं।

लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपेक्ष रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पक्षता के आधार पर विचार करेंगे और अपनी निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे (जसको वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे)। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय

पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन तय किए गए संभरण डेकों के सम्बन्ध में साक्ष्य पत्र स्थापित करने, समतुल्य रकमा जमा कराने की स्वीकृति और की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भूतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पालवान पर असंग-प्रलय भूतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। डेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भूतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस की वृद्धि सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए डेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए:—

“साक्ष्य-पत्र की प्राप्ति के बाद ————— महीने परन्तु अधिक से अधिक ————— के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31.12.86 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण डेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तें:

2(1) डेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन के भिल के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इनमें भारतीय अधिकारों का कमिशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए ओ कि भारतीय रूप में चुकाया जाना चाहिए।

भारतीय रूप या किसी अन्य मुद्रा में डेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। कय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टि-करण आदेश केवल अंग्रेजी में होता चाहिए।

2(2) प्रो० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए मुख्य निर्देश अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) बोली लगाने के लिए आमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनकी इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाए।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को अवांछित बोली वापस या गारंटीवा रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएंगी:—

(क) जहां आयातक के पास विश्ववनीय कारण हो या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल अनुरोध इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दलचस्पी न ले या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वहीन न हो जाए।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के प्रतिरक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया की अनुपयुक्त जल्दी उदाहरणार्थ आयात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अध्यादेश प्रकटा इस ढंग से भवनाई जाए। जिससे जहाँ तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

1. औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।
2. अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।
3. एक संभरक से सीधा कर।

किन्तु योंबे यह प्रस्तावित किया जाए कि ऋण की रकम में से वित्त-दान किए जाने वाले मास और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिल अधिप्राप्ति क्रियाविधि भवनाई जाए तो निधि की, अधिप्राप्ति तरीके (तरीकों) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा आवेदन पत्र भेजकर जिसमें उसके औचित्य भी दिए हों, निधि की पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाएगी।

मास और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिये बोलीकारों के लिये सूचनाओं और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली लगाने से सम्बन्धित सभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उसके अनुमोदन के लिये भेजेगी।

निधि का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र/वस्तुवेज आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को दो प्रतियों में भेजे जाने चाहिये।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1979-80 के लिये ओ० ई० सी० एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई० डी० पी०-17 के अधीन खोले गये अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिये जिसका ब्यौर नीचे खंड-6 में दिया गया है।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिये। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिये आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान-अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये।

2(6) संभरक को पात्रता:—

संभरक पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा ग्यायिक व्यक्ति होंगे या पात्र देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे और जिनका नियंत्रण पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा।

2(7) संविदा में घोषणा:—

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जायेगा :—

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभरित किया जाने वाला मास,.....में (पात्र स्त्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी भागे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है।

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क $\times 100$ और

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

मैं, अधोहस्ताक्षरी, और एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि..... (पात्र स्त्रोत देश का नाम) में..... (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।”

2(8) अपात्र स्त्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र देशों में बनी हुई सामग्री मिश्रित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संभरक आधार पर आयातित भाग 30 से कम हो :—

आयातित लागत बीमा भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क $\times 100$

संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य

खण्ड 3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शक्तें :

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिये:—

(क) ठेके को व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसाएफ) के बीच भारत येन रेलवे परियोजना के लिये येन क्रेडिट आईडीपी-17 (परियोजना सहायता) से संबंधित 14 मई, 1982 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिये और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसाएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईडीपी-17 से संबंधित 14-5-82 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक अफ इण्डिया, टोकियो द्वारा जारी किये जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किये जायेंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूची, सूचना और वस्तुवेजों को प्रस्तुत करने के लिये सहमत होगा जो कि एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर आईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में।

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिये कि जापान संभरक भारतीय वृतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिये सहमत है और इस उद्देश्य के लिये वह भारतीय वृतावास, टोकियो को, शामिल मास की सुपुर्गों के कार्यक्रम से अवगत करेगा और पोत-लदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व भारतीय वृतावास की सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोलतदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिये सहमत होना चाहिये और उनकी एक प्रति भारतीय वृतावास, टोकियो को भेजा जानी चाहिये।

खण्ड 4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिये निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय रेलवे और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो, विदेशी संभरकों द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण, फोटो प्रतियां, संगत बैंड आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां सहित जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भेजनी चाहियें।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिये और ठेकों की विषय-वस्तु के लिये अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कमियों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग भारतीय रेलवे विकास परियोजना के लिये येन क्रेडिट सं० आई० डी० पी०-17, (परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिये विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० सी० ई० एफ०) को संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिये भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड 5 विदेशी संभरकों को भुगतान साखपत्र क्रियाविधि :

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा रेल मंत्रालय, सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जायेगी। उसके बाद रेल मंत्रालय की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएए कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबन्ध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये अनुरोध करना चाहिये। सीएए एण्ड ए सम्बन्धित विदेशी संभरक के लिये संलग्न प्रपत्र में अनुबन्ध-4 में दिये गये के अनुसार अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिये बैंक आ

इण्डिया, टोकियो शाखा को सम्बंधित अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिये) में संलग्न प्रपत्र अथवा अनुबंध-6 (सेवाओं के लिये) में एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा। प्राधिकारपत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिये लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिये लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अप्रतिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ.ई.सी.एफ.) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सं० ए० ए० एंड ए० से प्राधिकारपत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिये उपर्युक्त क्रियाविधि सविद्या में संशोधन के लिये या अन्यथा रूप से आवश्यक समझे जाने वाले प्राधिकारपत्र/साखपत्रों के ऐसे सभी संशोधनों पर म्यात लागू होगी।

5(3) माल का पोतलवान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिये बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाये गये तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों का लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र को खोलने, रख-रखाव और परिवालन पर किये गये सभी खर्च विदेशी संभरकों या आयातकों के लेखे में जायेगा। अतः भारतीय बैंक, टोकियो संभरक बैंक के सभी खर्च प्राप्त करेगा, दस्तावेजों को संभाल के रखने और मौल-सौल करने और अन्य आकस्मिक खर्च भी संभरकों द्वारा किये जायेंगे।

संभरकों को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क माल को खाने के भुगतान की तिथि और ओ.ई.सी.एफ. द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का ध्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जायेगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा ध्याज भुगतान पर किया गया खर्च भारतीय रेलवे (रेल्वे खंड-6) (4) से प्राप्त किया जायेगा।

खंड 6—रुपया निक्षेप कामे के लिए उत्तरदायित्व :

6(1) भारतीय बैंक टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार आयातक के प्राधिकृत बैंकर के परकाय्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बखाने में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी/पीएन/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किये जाते हैं।

संभरक का भुगतान को गई विदेशी मुद्रा का समतुल्य रुपया जमा करवाने पर बैंकर से प्राप्त कुल जहाजरानी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ही आयातक आयातित माल की गुणवत्ती से सकता है। इन प्रक्रिया से किसी भी छूट के लिये सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, गंसद मार्ग, नई दिल्ली से अनुमति लेनी चाहिये।

विदेशी संभरक को किये गये येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिये भपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख

को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक, 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात..... की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जायेगा वह 'के डिपोजिट्स एंड एडवांसिज 843 मिजिल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटस्ट्रा एंडोड परचेज ग्रन्डर क्रेडिट्स लोन एप्रोमेन्ट लोन फ्रीम दि गर्वेनमेंट आफ जापान 2.68 बिलियन येन क्रेडिट सं० आई डी० पी० 17' फार भारतीय रेलवे विकास परियोजना' होता चाहिये।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-1968, सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68 सं० 132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 सं० 74-आई टीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आईटीसी (पीएन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिये। लेकिन उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना 31-5-74 में उल्लिखित व्याज प्रभार की गणना करने और जमा करने से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होगी, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किये गये आयातों के संबंध में किसी भी प्रकार के व्याज प्रभार वसूल करने योग्य नहीं है।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किये जाने के बाद सात दिनों तक के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह प्रतिष्ठित धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाये। जालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिये कि सार्वजनिक सूचना सं० 132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना जालान के कालम 'घन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो)' के पूर्ण व्योरे में निरपवाद रूप से निविष्ट की गई है। खजाना जालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिये :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में भपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किये जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सं० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किये गये प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना जालान, रुपया जमा करने का साध्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सं० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिये।

टिप्पणी:—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से आयातकी सूचना और अप्रतिवर्तनीय पोतलवान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सं० ए० ए० एंड ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जायेगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को साइसेस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेप की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एस' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई को भेजना चाहिए। भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक आफ इण्डिया टोकियो को दिए गए ध्याज प्रभार के अनुसार ही येन भुगतान के तुल्य रुपये की गणना की उपर्युक्त खंड 6 की कंडिका 6(1) में निर्धारित तरीके से

की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, के नाम में जमा कर दिया जाएगा। और सी०ए०ए० एंड ए० इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परामर्श जारी करेगा।

खण्ड 8 : विविध व्यवस्थाएं :—

8(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :—आयातक का पोतलवान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, विस मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, ससद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) विशेष शर्तों को अधिसूचित किए जाने वाले सम्भरण :— लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से सम्भरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने से जाने में सम्भरक पर प्रभाव डालती हो।

8(3) विवाद :—यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सम्भरक के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले सम्भरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में भुगतान की शर्तों के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश :—आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन फ्रेडिट समझौते (परियोजना सहायता) स० आई० डी० पी० 17 के अधीन सभी आचार्यों को विदेशी आर्थिक निगम निधि जापान (ओ०ई० सी० एफ०) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना चाहिए।

8(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची :

1. अनुबन्ध 1, पात्र स्त्रोत देशों की सूची
2. अनुबन्ध-2, अधिप्राप्ति के लिए मुख्य सागंवरान
3. अनुबन्ध-3, प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबन्ध-4, प्राधिकारपत्र का प्रपत्र
5. अनुबन्ध-5, साखपत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबन्ध-6, साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ० पी० ई० सी० से शिशु विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा,

मिश्र

मोरोको

तुनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

वरण्डी

कैमेरून

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र

चाद

कमोरो द्वीप समूह

कांगो डहिले का गणतंत्र

भूमध्य गिनी (1)

इथोपिया

जाम्बिया

षाना

गिनी

ग्राइवरी कोस्ट

केनिया

ले सोथे

लाइबेरिया

मालागासी गणतंत्र

मालावी

माली

कोस्टारिका

स्यूडा

डोमिनिकान गणतंत्र

ई० आई० साल्वेडोर

ग्वाटे लोप

ग्वीडे माला

हेती

होन्डुरस

मारिटेनिया मारीशस

मुजाम्बीक

लाइगर

पुर्तगाली गिनी.

रिबूनियन

रोजेशिया

रवान्डा

सेंट हेलेना और ट्रिप (2)

साबोटीम और भिन्वाहन

सेनेगाल

सेचोलाञ

सियरा लिओन

सीमालिया

सूडान

स्वाजी लैण्ड

टेरी आपर्लस और इसास

टोमो

युगाण्डा

तंजानिया संयुक्त गणतंत्र

अपर बोल्डा

लाइरे गणतंत्र

जाम्बिया

3. अमेरीका उत्तरी और केन्द्रीय

बाहमस

बारबाडोस

- बेसीज
बेरमुड
4. दक्षिणी अमेरीका
अर्जेन्टिना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलोम्बिया
कालक लैण्ड द्वीप समूह
जैमेका
मार्टिनिका
ओन्सिक्तों
नीदरलैण्ड एन्टिलीज
निकारगुवा
पनामा
सेंट पियरी और मिक्योलोन
ट्रिनिडाड और टोबोगो
वेस्ट इण्डीज (शाख) एन्मार्ईई
(क) संबंद्धित राज्य (1)
(र) अश्विमे (2) टोगो
फ्रांसोसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सुरिनाम
उरग्वे.

5. मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटेड अरब एमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

- (1) पहले स्पेनी मिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पी द्वीप सहित,
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित:—
असन्शन, ट्रिस्टन डा इन एक्सोसिबिलिस, नाइटिनोल गफ ।
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरब बीनेरे न्यूराकाओ सांछा, सेन्ट मार्टिन
(दक्षिणी भाग)

6. दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
माल द्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका
7. मध्य पूर्वी एशिया
अरबी
हांगकांग
खमैर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
8. ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी

- गिल्बर्ट और हलाइस द्वीप
फांसिलो बोलिवेशिया (6)
नीह
न्यूवलेगोनिया
न्यू इन्डोसिल हैसिल (भा० और कै०)
फैश्यू
पसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (8)
वासुवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (भा०)
टोंगा
वालिस और फुतुना
पश्चिमी सभाओं
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिनापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

9. यूरोप
साइप्रस
सिआल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
टुर्की
यूगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप समूह एंटिगुवा, जोभिनिका, सेनाडा, मेल्ड किट्टस (सेंट किट्टाके), सैंथिस-ए ग्युला, सेंट नुसिशा और सेन्ट विन्सेन्ट ।
(2) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात सेमान, तुर्कस और काईकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह ।
(3) अजमान, बुबई, फुजाइरह, रस अल खेमाह, शारजाह और उम अल क्वैयन ।
(4) अदन और विभिन्न सुलतनत और अमोरात सहित ।
(5) सोसायटी द्वीप समूह (तह्तिी सहित) का शामिल करने हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटू जम्होरिय और मकेस द्वीप समूह ।
(6) पसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कोरोकोर द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के उत्तर या सहयोगी देश

- अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियन अरब गणतंत्र
रीमान
न.इजोरिया
इक्वैडोर
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
यमनवादी
इण्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

श्री० ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना श्रृणु के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन।

1 विज्ञापन

आवृत्त खूली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी सविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए श्रृणी देश में सामान्य प्रचार के लिए नाम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र शीत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2 बोली के दस्तावेज और सविदाएं

2.1 बोली बाण्ड और गारंटिया

बोली बाण्ड या बोली की गारंटिया आधारण आवश्यकताएं हैं। लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खोलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड प्रथम गारंटियां हस्तगत बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

2.2. सविदा की शर्तें

सविदा के प्रकाशन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दो नई सविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और यदि आयातक द्वारा कोई इंजिनियर नियुक्त किया है तो उनके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। सविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निदेशन विनियमों में किया गया है के अनिश्चित परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपर्युक्त शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 सविदाओं की किस्म और आकार

सविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदिन सबों के या एक मूल्य कीमत के या सविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर प्रदान किये जाने वाले माल या सेवाओं के अनुसार की जा सकती हैं और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई मादद की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होना चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपुष्टि पर मुख्यतः आधारित सविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि की स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपकरण और निर्माण के लिए इसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल सविदाएं (टर्नकी सविदाएं) यदि श्रृणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे नियंत्रक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान श्रृणु की रकम में से किया जाना है (जिसे इनके बाद 'पात्र संभरक' कहा गया है), पात्र शीत देशों के राष्ट्रिक हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे -

- (1) भविष्यतः किए गए शीत देशों का एक बड़ा भाग पात्र शीत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्णकालिक निवेशकों का बहुमत पात्र शीत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।
- (3) ऐसे व्यापिक 'व्यक्तियों' का पञ्जीकरण पात्र शीत देशों में होगा।

3 सविदा की कीमत

(घ) सविदा कीमत जापान में दर्शाई जानी चाहिए। यद्यपि कि सविदा कीमत या वह भाग जो ठेकेदार श्रृणी के देश में खर्च करेगा श्रृणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मुख्य समझौता कटिबाण बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है श्रृणी वाली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि सविदा के प्रमुख लागत अवयवों

अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों को कोई परिवर्तन होता है तो सविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होगी।

कीमतों के समझन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सलाह के लिए सविदाओं में कीमतों के समझन का उच्चतम निर्धारित सीमा की भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन विविध पात्रों के लिए सविदाओं में इस प्राण की उच्चतम निर्धारित सीमा का प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एक वर्ष के अन्दर सुगुं किए जाने वाले माल के लिए मुख्य समझन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग निर्देशन विनियम उन विविध उपायों के परिचय का आकास नहीं करती हैं जिनके द्वारा सविदा मूल्य समझित किया जा सके।

(ग) बीमा सकल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विविध हस्ताक्षरित सविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश को भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड की स्वीकार्य हैं।

3.3 प्रत्येक सविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा -

संभरक एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी/हमारी कम्पनी पात्र संभरक है क्योंकि शीत देशों का प्रतिशत () पात्र शीत देश () के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है और () प्रतिशत () नि-देशक (पात्र शीत देश के राष्ट्रिक हैं और मेरी (हमारी) कम्पनी (पात्र शीत देश) में पञ्जीकृत कराई गई है।"

4.1 मानदण्ड - यदि उन राष्ट्रीय मानदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाले पूर्ण वस्तुएं या मापदण्डों की कीमतें के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 बाण्ड नामों का प्रयोग यदि विशेष प्रकार के फानस पुजों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खान आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक विधि की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केना बाण्ड नाम, सूची संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। यदि बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पूर्ण वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और काम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उत्तम हैं।

4.3 गारंटी निष्पादन बाण्ड और रोकें रखी गई धनराशि। दायित्व कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या ती वैक गारंटी द्वारा/निष्पादन बाण्ड द्वारा हो जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार निश्चय होगी, लेकिन ठेकेदार में इसी पात्र जाने के मामले में श्रृणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानतों अवधि को पूरा करने के लिए सविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बाण्ड की धनराशि को बोली की दस्तावेजों में निश्चित किया जाना चाहिए।

भाषा की सफाई के लिए मंथनार्थों में आम तौर पर वा. बोझनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिफल माना जाए। रोक रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाना है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली अति : श्रृणों को जब कार्य पूर्ण होने या सुदुर्घटों में बंद होने के कारण फालतू श्रृणों, राजस्व की हानि या अथवा लाभों में मुकमान होना है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली अति से संबंध प्राप्तदान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा इससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य श्रृणों को लाभकारी हो, तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. वाष्पकारी परिस्थिति : बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा कि शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पाटों द्वारा अपने वास्तवों को न पूरा करना उस हालत में एक बूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी बूक विचित्र स्थितियों में (फोर्स मज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है)

7. झगड़ों का निपटान : झगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह बोझनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्भर के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या : बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए की कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय बोली तैयार करने के लिए अनुमत समय अधिकार संविदा की महत्वत, और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भर्ती-भांति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमत समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली खोलने की क्रियाविधि : बोलियों की अन्तिम पाबली के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोली जानी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी बैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि और से पट्टी जानी चाहिए और उसकी रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन : बोली खोलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार

किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े, आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के जिय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेकिन बोलीकार या उसकी बोली के आरोप एवं मुख्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रिया-विधि : कानून द्वारा यथा उपेक्षित को छोड़कर बोली खोलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित मिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों के औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जांच बोलियों के खोलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक अमानत की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित है और क्या बोलियों सामान्यता अथवा रूप से सही है, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टीकरण के अनुसार नहीं हैं या उनमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विमर्शण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं : पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति से आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास संबंध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान : बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितिय गलतियों के लिए संमंजित बोली की कीमत के अनिश्चित अन्य बात जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य-क्षमता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विद्यमानता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदंड के अनुसार रूप से की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई संमंजित कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मुख्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर श्रृणों द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना श्रृणों द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनियम की दर सरकारी जोड़ द्वारा प्रकाशित विषय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खोलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू हानी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना : बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि श्रृणों सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उमी विशिष्टीकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित

कोमल से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए सब शौचित्य देने चाहिए जहाँ (क) बोलियाँ, बोली दस्तावेज के आणव के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो श्रुणी को चाहिए कि वह उन कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिसे अस्वीकृत सिद्ध की गई है और या तो निगमिकरण के परिवर्तन पर या परिशोधन के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आणवण में मांगी कई पुण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद श्रुणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक वम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यवर्धित बोली पर निश्चित की गई है और जो अमला और वित्तीय साधनों के उचित गानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होता चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विनिश्चितकरण में निर्धारित पण्य-वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मे-दारी से।

अनुबन्ध 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्राप्यता पत्र

मं० दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियन्त्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यु० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:—येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के
अन्तर्गत आपान से का प्रायास।

महोदय,

उपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं० (परियोजना सहायता) के अधीन
... से
जो कि के प्रायास
के संबंध में (बैंक का नाम)
जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ड) में संबंध समुद्रपार संभरक के
नाम में साख पत्र खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी
करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ध्योरे प्रस्तुत करने हैं—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की मख्या दिनांक और मूल्य यह नगरीज जिस तक वैध है।
- (ग) प्रतिन के तरीके क्या वह सीधे
क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित
है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण नहीं
यह मकेदित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय हो तो
उपयुक्त न्यूनतम लफलीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया
है।

(घ) मात्र का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) मात्र का उद्देश्य देश।

987 GI/82—2

(च) यदि कोई हो तो पात्र में हलर ओत दणो से प्रायास संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल अज्ञात पर्यन्त निशुल्क मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमिशन की धनराशि (येन में)।

(झ) वास्तविक अज्ञात पर्यन्त निशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता —

- (1) राष्ट्रिकता।
- (2) पात्र ओत दणो के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शायरों का प्रतिशत।
- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या संभरक का निवास स्थान।
- (4) उन निदशकों का प्रतिशत जो पात्र ओत वेनों राष्ट्रिक हैं।

(ठ) व भुगतान शर्त और सभावित विधि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होगा।

(ड) सुपुर्वगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ध) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक) सेट की संख्या और उभवा निपटान दिखाने हुए।

(ण) पीतलवान धनुवेश बाहनाम्तरण/पाट शिपमन्ट की इत्सुकि की गई है या नहीं निदिष्ट कीजिए।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(व) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हाँ, तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संवर्ध जिसके अन्तर्गत ओईसीएफ को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध 4

(प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र)

संख्या एक

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

बैंक ऑफ इण्डिया

टोकियो शाखा,

टोकियो, (जापान)

विषय:— येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) श्रुण करार सं०
... . के अधीन आयात साध-पत्र खोलने के लिए प्राधि-
कार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद द्वारा, यथा खुले जाने ध्योरे के अनुसार सर्वधो

(.....) धन व्यय करने हैं) का कुल धनराशि से अधिक नहीं है, उसे निम्नलिखित दस्तावेजों में माध्य भेजा जाना है:-

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

कमान अर्न्त बोर्ड, समुदाय पोतजदान बिल विनियमों द्वारा अधेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिह्नित "फैट एवं नाटिकार्ड"

अन्य दस्तावेज जिसमें से तक

तक खदान का सम्पादन किया गया हो सविदा संख्या (यदि कोई हो) के सदर्थ में मर्यादित विवरण आगत पोतजदान स्वीकृत है, वाहनलक्षण स्वीकृत है।

पोतजदान बिल जो से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए। अधेशों को 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इन क्रेडिट के अन्तर्गत सभी डाकट और दस्तावेजों पर बहुराशनी होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साक्ष्यपत्र सं. दिनांक 19 के अन्तर्गत निम्नलिखित गया और आयात सबसे संख्या (संख्या) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तात्मन्वीय नहीं है।

हम एतद्वारा बचन देते हैं कि अप्र क्रेडिट के अन्तर्गत और इसका शर्तों का अनुपालन करके निम्नलिखित गए सभी डाकट प्रस्तुत करने पर और आदेशों को दस्तावेजों की सुदृढी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

अब तक अथवा रूप से विश्वासपूर्वक न बताया जा कि क्रेडिट (युनि-फार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार् डाकुमेंटरी क्रेडिट (1974 रिजिजन) इन्टरनेशनल सेम्वर ऑफ फार्मसे, पब्लिकेशन, सं. 290' के अधीन है।

सोचा करने वाले बैंकों के लिए विशेष अनुबंध -

उचित श्रद्धा कर्ता के अंतर्गत जारी किए गए धनपत्रों की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग विधि द्वारा हमारे धनगतन के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम बचन देते हैं कि इन सीमा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अधेशों के अनुसार डाकट का धनराशि को जमा देगे।

2. सोचा करने वाले बैंक को यह बताया जाएगा हम डाकट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और हमने नाम एक प्रमाणपत्र अत्र भेजे कि शेष दस्तावेज रा धे हों। हवाई डाक द्वारा को भेज दिए गए हैं।

3. इन क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के अपने धन/समर्थक के लेखों के लिए हैं।

संख्या

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा-

प्रमाणित हस्ताक्षर

भुगतान में

यह भुगतान हमारे साक्ष्यपत्र सं. का उचित सब है।

प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि- से जो कि कुल

सविदा भुगतान के- प्रतिशत है

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की प्रतिम तिथि

संभवर्तनी भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि- से

जो कि कुल सविदा भुगतान का प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की प्रतिम तिथि

3. धनराशि- से

धनराशि- से

सविदा के कुल भुगतान का- प्रतिशत है।

शिर्षक- - पोतजदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इन सबके दस्तावेजों को प्रावश्यकता नहीं है।

अनुबंध 6

(अपर भा. सं. 1. 0. 1970 एवं सं. 0-1)

(अपरभा. सं. 1. 0. 1970)

(पैकाओं के लिए लाभ)

दिनांक-

भैया म,

यह साक्ष्यपत्र आपको और विशेष आधिकारिक मर्यादा विधि के बीच हुए आयात करार सं. दिनांक- के अन्तर्गत में जारी किया गया है।

(समर्थक का नाम व पता)

प्रिय महोदय,

हम आपका सूचित करने हैं कि हमारे नाम से निकालने के लिए पूर्ण व्यय के लिए लाभकारी डाकट एवं साक्ष्यपत्र द्वारा उपलब्ध करवा सकेंगे के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साक्ष्यपत्र सं. को भेज दिया है जो कि (यदि कोई हो) को कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

हमारे नाम भुगतान अधिभार (संख्या- और परियोजना-) में सम्बंधित दस्तावेजों को भेजने करवा है सोचा राय करने के लिए डाकट- से अपने प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

यदि डाकट और दस्तावेज सार्वजनिक साक्ष्यपत्र सं. दिनांक- के अन्तर्गत भुगतान किया गया है, वे चिह्नित होने चाहिए

यह क्रेडिट हस्तात्मन्वीय नहीं है।

हम एतद्वारा बचन देते हैं कि इन क्रेडिट के अन्तर्गत हमारी शर्तों का अनुपालन करके भुगतान गए सभी डाकट प्रस्तुत करने पर और आदेशों को दस्तावेजों की सुदृढी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

अब तक अथवा रूप से विश्वासपूर्वक बताया न जाय यह क्रेडिट "युनि-फार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार् डाकुमेंटरी क्रेडिट (1974 रिजिजन) इन्टरनेशनल सेम्वर ऑफ फार्मसे, पब्लिकेशन, सं. 290' के अधीन है।

सोचा करने वाले बैंक को विशेष अनुबंध

हम एतद्वारा बचन देते हैं कि इन क्रेडिट के अन्तर्गत हमारी शर्तों का अनुपालन करके भुगतान गए सभी डाकट प्रस्तुत करने पर और आदेशों को दस्तावेजों की सुदृढी पर विधिवत स्वीकार किए जाएंगे।

के अनुसार किए जाने चाहिए। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उद्युक्त निष्पादन के विवरण के वजाए सामग्री विवरण की आवश्यकता है।

2 उपर उल्लिखित श्रेणी समझौते के अधीन जारी किए गए वचनपत्रों पर के उपबंधों के अनुसार आवश्यक आर्थिक सहयोग विधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम शान्तों में घनराशि का मौल तौल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं।

3 उपर्युक्त पर 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और उसीसे हमें उनकी प्राप्ति के पुरस्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4 इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खाचें आयातक/भारती के लेखों के लिए हैं।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा, -----

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साखपत्र सं-----का एक अतिरिक्त भाग है।

1 प्रारम्भिक भुगतान

घनराशि ----- येन

कुल संविदा मूल्य का-----प्रतिशत है।

अपेक्षित दस्तावेज सामग्री विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि-----

2 भुगतान विधि

संपूर्ण योग की घनराशि-----येन

कुल संविदा मूल्य का-----प्रतिशत निम्न

प्रकार से भुगतान किया जाना है --

देय घनराशियाँ----- अन्तिम भुगतान तिथि

येन -----

पहली किश्त येन -----

दूसरी किश्त येन -----

अपेक्षित दस्तावेज (शुष्की अथवा उनके अनुरोधित प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रत सलक्ष है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक -----

सेवा में सदस्य -----

(संभवतः का नाम और पता)

संदर्भ----- अणु करार सं----- के अन्तर्गत-----

परिप्रेक्ष्य से संबंधित----- के नाम में-----

येन के लिए----- द्वारा जारी किए गए साखपत्र की

सं----- दिनांक-----

में अघोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (अणु) एतद् द्वारा-----

और----- के बीच समझौता सं-----

दिनांक----- में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार

समुद्रवार आर्थिक सहायता विधि द्वारा -----
की घनराशि) ----- येन केवल) प्राप्त करने
के लिए एक निष्पादन विवरण जारी कराया है।

(-----)

(आपने)

द्वारा-----

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश -----

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें सलक्ष 'पक्ष' में दर्शाया जाएगा।

महानिरीक्षण, सी, मुख्य निरीक्षण,
आयतन-निर्माण

नवाग राय, संयुक्त मुख्य निरीक्षण
आयतन-निर्माण

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 55-ITC (PN)/82

New Delhi, the 16th November, 1982

Subject.—Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Yen 2.68 billion for the Implementation of the Indian Railways Development Project.

File No. IPC/23 (35)/82. The terms and conditions governing the issue of import licence in respect of import of goods and services under the OEGP Loan Agreement No ID-P. 17 (the Indian Railways Development Project) of Yen 2.68 billion as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 55 ITC (PN)/82 Dated the 16th November, 1982

Licensing Conditions in Respect of imports of Goods and services under the Yen Credit of Yen 2.68 billion for the Implementation of the Indian Railways Development Project

Section—I : General Conditions

I (i) The Yen credit of 2.68 Billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Indian Railways Development Project is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this Credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the Credit.

I (ii) Import licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this Credit should not exceed 3,000 million (CIF).

The rupee value of the I/L shall be determined with ref. to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the I/L and indicate in the body of the Import Licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dt. 6-6-74, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence (s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 17". The first and 2nd suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter

from the CCI&E forwarding the import licence to Indian Railways a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section)

I (iii) Import licence(s) can be issued only in favour of Indian Railways on C.I.F. basis.

I (iv) Depending on the convenience of Indian Railways more than one I/L may be issued under this credit, but the total value must not exceed 3,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I (v) The extension of the validity of import licence, may on application by Indian Railways, be granted upto 31-12-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I (vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the I/L duly attested by the Licensing Authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the I/L. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the I/L. Freight and Insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian Licensee on the Overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the Overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the I/L. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the I/L to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the I/L such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of Letter of Authority for the establishment of Letter of Credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent etc. in respect of supply contracts entered into under the I/L.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the I/L. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian Importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

" months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-86.

Section II . Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II (i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should ex-

clude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances, the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The main guidelines for procurement of goods and services under the OFCE Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

If (iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedure :

- (a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- (b) Where the number of qualified suppliers is limited.
- (c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- (d) Where, in addition to the cases (a), (b) & (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate.

- (i) Formal Selective International Tendering.
- (ii) Informal International Competitive Procurement.
- (iii) Direct purchases from a single supplier.

However, prior approval of the Fund shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the Loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by a duly authorised person together with its reasoning.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the importer shall submit to the Fund for its approval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding.

The application/documents should be sent in duplicate, to the Department of Economic Affairs (Japan Section) for obtaining the approval of the Fund.

II (iv) The payment to the overseas supplies should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OFCE Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.17 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II (v) Only one contract should be entered into against the I/L. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 53—ITC(PN)/82

New Delhi, the 23rd October, 1982

Subject:—Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of ¥ 6.0 billion for Telecommunications Project (V) of the DGP&T.

File No. IPC/23(34) 82.—The terms and conditions governing the issue of import licence in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of ¥ 6.00 billion for telecommunications Project (V) of the DGP&T extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller
of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC
NOTICE NO 53—ITC(PN)/82

Dated the 23rd October, 1982

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of ¥ 6.0 Billion for Telecommunications Project (V) Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan.

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of ¥ 6.0 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 6,600 million (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.19". The first and second suffix to the licence code will be "S/IC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed ¥ 6,600 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-86. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will be authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

".....months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-86.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However prior approval of the Fund shall be obtained, if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan, submitting to the Fund an application for

approval of procurement method(s) signed by duly authorised person together with its reasoning.

Immediately after conclusion of Loan Agreement the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its review. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the DEA (Japan Section) for transmission to/obtaining approval of OFCI.

II(iii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 19 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(v) Eligibility of Supplier.—Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(vi) Declaration in Contract.—The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries".

II(vii) Permissible imports from non-eligible source countries.—Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts :

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

- (a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 14th May, 82 concerning the Yen Credit No. ID-P. 19 (Project Aid) for Telecommunications Project (V) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.
- (b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P. 19 dated 14th May, 82 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).
- (c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under Yen Credit arrangements by the Government of

India on the one hand and the OECF on the other (d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vi).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF :

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV(ii) The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. ID-P. 19 (Project Aid) for Telecommunication Project (V).

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure :

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economics Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation.

The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of credit will be either to the

Equatorial Guinea (1)
 Ethiopia
 Gambia
 Ghana
 Guinea
 Ivory Coast
 Kenya
 Lesotho
 Liberia
 Malagasy Republic
 Malawi
 Mali
 Mauritania, Mauritius
 Mozambique
 Niger
 Portuguese Guinea
 Reunion
 Rhodesia
 Rwanda
 St. Helena and dep. (2)
 Sao Tome and Principe
 Senegal
 Seychelles
 Sierra Leone
 Somalia
 Sudan
 Swaziland
 Terro. Afars and Issas
 Togo
 Uganda
 Un. Rep. of Tanzania
 Upper Volta
 Zaire Republic
 Zambia

III. AMERICA, North and Cent

Bahamas
 Barbados
 Belize
 Bermuda
 Costa Rica
 Cuba
 Dominican Republic
 El Salvador
 Guadeloupe
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Jamaica
 Martinique
 Mexico
 Netherlands Antilles
 Nicaragua
 Panama
 St. Pierre & Miquelon
 Trinidad and Tobago
 West Indies (Br.) n.i.e.

(a) Associated States (4)

(b) Dependencies (5)

IV. AMERICA, South

Argentina
 Bolivia
 Brazil
 Chile
 Colombia
 Falkland Islands

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustace, St. Martin (Southern part).

(4) Main islands, Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(5) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

French Guiana
 Guyana
 Paraguay
 Peru
 Surinam
 Uruguay

V. ASIA, Middle East

Bahrain
 Israel
 Jordan
 Lebanon
 Oman
 Syrian Arab Republic
 United Arab Emirates (6)
 Yemen Arab Republic
 Yemen, People's D.R. (7)

VI. ASIA, South

Afghanistan
 Bangladesh
 Bhutan
 Burma
 India
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka

VII. ASIA, Far East

Brunei
 Hong Kong
 Khmer Republic
 Korea, Republic of
 Laos
 Macao
 Malaysia
 Philippines
 Singapore
 Taiwan
 Thailand
 Timor
 Viet-Nam, Republic of
 Viet-Nam, Democratic Republic.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
 Fiji
 Gilbert & Ellice Is.
 French Polynesia (8)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (US) (9)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. Europe

Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(6) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(7) Including Aden and various sultanates and emirates.

(8) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(9) Trust Territory of the Pacific Islands : Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a) Member or Association Countries of OPEC

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon

Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS FORMULATED BY Q.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1 Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after bids have been opened.

II-2. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II-3. Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1 Contract Price

- (a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

- (b) Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ percent (_____ %) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country) and _____ percent (_____) of the directors are nationals (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spareparts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract

IX-1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids.

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX-2. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX-3. Clarifications or Alternation of Bids.—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened, only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX-4. Procedures to be confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX-5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX-6. Post-qualification of Bidders.—In the absence of pre-qualifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the

capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX-7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX-8. Rejection of Bids.—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b), there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX-9. Award of Contract.—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY DATE

NO

To

The Controller of Aid Accounts and Adult,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub.—Import of _____ from Japan under the
Yen Credit No. _____ (Project Aid) _____

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen Credit No. _____ (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ (Name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned.

(a) Name and Address of the Indian importer.

- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen)
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen, if any).
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers.
- (k) Name and address of the Overseas Supplier
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the Supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No. date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

Government of India

Ministry of Finance

Department of Economic Affairs

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject.—Import under Yen Credit Project Aid—Loan Agreement No. _____ Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement to you by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers, if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may, therefore, be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—

Pours faithfully,

(Accounts Officer)

Copy forwarded to

1. Importer—_____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2 Importers' Bank—_____. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc., abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan 2.68 Billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P 17 for 1979-80.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The Banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying

their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V
(Form OECF-LC I)

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date :

To _____
_____ dated _____
_____ between (Borrower) and THE
(Name and address of the OVERSEAS ECONOMIC CO-
Supplier) OPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clear on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight and Notify

Other documents

evidencing shipment of [brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any)] from _____ to _____

Partial shipments are _____ permitted. Transshipment is _____ permitted.

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____, dated _____, irrevocable credit No. _____, and Import Reference No. (s). _____ (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter

of Credit issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the draft in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to _____

3. All banking charges under this credit are for the account of the importers/suppliers.

Yours faithfully,

_____ (a commercial bank)

By :

_____ (Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____

I. Initial Payment

Amount Y _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount Y _____
being _____ % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount Y _____
being _____ % of the total
contract price.

NOTE : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI
(Form OECF-LC II)

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

Date :

To

_____ This Letter of Credit has been
_____ issued pursuant to Loan Agree-
_____ ment No. _____
_____ dated : _____
(Name and address of the between (Borrower) and THE
Supplier) OVERSEAS ECONOMIC CO-
OPERATION FUND.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say Yen _____) available

by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. with regard to—Project). Drafts must be presented for negotiation not later than all drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. dated.....".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No.290."

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment (s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
- 3 A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.
- 4 All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplies.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____
(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being % of the total contract price
Required documents : beneficiary's Statement
Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Y _____

being— — — — — % of the total contract price to be paid as follows :

Amount due	Latest presentation date
_____	_____

1st Instalment : Y _____

2nd Instalment : Y _____

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority),
a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

Ref . No.

To _____

(Name and address of the supplier)

Re : Letter of Credit No., dated,
issued by _____
for Y _____ in favour of
_____ concerning _____ Project
under Loan Agreement No.

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle _____ to receive the sum of Y _____ (Yen _____ only) from THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No., dated _____, between _____ and _____

(Borrower)

By : _____

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

(MANI NARAYANSWAMI),
Chief Controller of Imports & Exports
TAKHAT RAM,
Jt. Chief Controller Imports & Exports.

